गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 295
दि. 26.02.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका का 80,952 करोड़ का मेगा बजट पेश, विकास परियोजनाओं को मिली बड़ी रफ्तार

(जीएनएस)। मुंबई। देश की सबसे समृद्ध नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 80,952.56 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया है। यह पिछले वर्ष के 74,427 करोड़ रुपये के बजट से 6,525 करोड़ रुपये अधिक है, जो लगभग 8.77 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। चार वर्षों बाद यह पहला अवसर है जब निर्वाचित प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बजट पेश किया गया। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इसे एक रणनीतिक और दूरदर्शी बजट बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ मुंबई का निर्माण करना है।

इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर है। कुल बजट में से 48,164.28 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो कुल बजट का लगभग 60 प्रतिशत है। यह राशि सड़क, पुल, परिवहन, जल निकासी, अस्पताल, शिक्षा और शहरी विकास परियोजनाओं में निवेश के लिए उपयोग की जाएगी। वहीं, 32,698.44 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों का वेतन, नागरिक सेवाओं का संचालन और रखरखाव शामिल है। इस वर्ष अनुमानित राजस्व आय 51,510.94 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.35 प्रतिशत अधिक है।

बीएमसी की आय के प्रमुख स्रोतों में ऑक्ट्रॉय के बदले मिलने वाला मुआवजा, डेवलपमेंट प्लान फीस और प्रीमियम,

संपत्ति कर और निवेश से मिलने वाला ब्याज शामिल हैं। ऑक्ट्रॉय मुआवजे से 15,550.02 करोड़ रुपये, डेवलपमेंट प्लान फीस से 12,050 करोड़ रुपये, संपत्ति कर से 7,000 करोड़ रुपये और निवेश पर ब्याज से 2,572.23 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। इसके अलावा जल और सीवेज कर, लाइसेंस शुल्क और सरकारी बकाया से भी महत्वपूर्ण आय होने की उम्मीद है। संपत्ति कर को राजस्व का प्रमुख स्तंभ माना गया है, जिसमें इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

इस बजट का सबसे चर्चित पहलू बीएमसी की सावधि जमा (एफडी) का उपयोग है। बीएमसी के पास वर्तमान में 81,449.32 करोड़ रुपये की एफडी जमा है, जिसमें से 36,623.09 करोड़ रुपये विकास परियोजनाओं के लिए निकाले जाएंगे। यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर एफडी को तोड़कर बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया जाएगा। बीएमसी प्रशासन का कहना है कि मुंबई जैसे महानगर के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए इस राशि का उपयोग आवश्यक है, जबकि शेष राशि को भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

बजट में मुंबई के परिवहन और सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के अगले चरणों के लिए 4,700 करोड़ रुपये और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) के लिए 2,650 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना के पूरा होने से उपनगरों के बीच यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर लगभग 20 मिनट हो जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाओं के लिए 5,690 करोड़ रुपये और शहर के सड़कों के कंक्रीटीकरण के लिए 5,520.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा के लिए 4,248 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7,456 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बीएमसी कई बड़े अस्पतालों के पुनर्विकास पर काम कर रही है, जिसमें सायन अस्पताल, एम.टी. अग्रवाल अस्पताल और भांडुप में नया मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम को और मजबूत किया जाएगा, जिससे लाखों नागरिकों को समय पर जांच और उपचार की सुविधा मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। मुंबई की वायु गुणवत्ता में सुधार और 'नेट जीरो' लक्ष्य की दिशा में 159 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है। देवनार में वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कचरा प्रबंधन की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए BEST उपक्रम को 1,000 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग दिया गया है। यह सहायता बस सेवाओं के विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए उपयोग की जाएगी। साथ ही, कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए BEST बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी, जिससे शिक्षा तक पहुंच आसान होगी।

बजट में शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल क्लासरूम, साइंस लैब अपग्रेडेशन और छात्रों को टैबलेट वितरण जैसी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। नगर निगम के 1,203 स्कूलों के 7,953 क्लासरूम को डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे छात्रों को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा 190 साइंस लैब का आधुनिकीकरण और छात्रों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल है।

अरुणाचल की महिलाओं का अपमान करने वाले दंपति गिरफ्तार, देशभर में आक्रोश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं के साथ नस्लीय टिप्पणी करने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रूबी जैन और उसके पति हर्ष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज में मौजूद नस्लीय भेदभाव की मानसिकता को उजागर करने वाली एक गंभीर घटना के रूप में सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जो इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सोशल मीडिया पर इस मामले की व्यापक चर्चा होने लगी। वायरल हुए वीडियो में आरोपियों को अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और नस्लीय टिप्पणियां करते हुए देखा गया, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। यह घटना केवल तीन महिलाओं के अपमान का मामला नहीं, बल्कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के सम्मान और पहचान से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मुद्दा बन गई है। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और दोषियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि नस्लीय भेदभाव और अपमान जैसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गिरफ्तारी से पहले आरोपी हर्ष सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि उन्हें अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी है और यह घटना 'हीट ऑफ द मोमेंट' में हुई। उन्होंने यह भी कहा कि वे दिल्ली पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि, उनके इस बयान के बावजूद समाज के विभिन्न वर्गों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे एक गंभीर सामाजिक अपराध बताया है। लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं केवल माफी मांगने से समाप्त नहीं होतीं, बल्कि इसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करने से पहले सौ बार सोचे।

इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी तुरंत संज्ञान लिया और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय शुरुआत से ही पीड़ितों और दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

'कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस' अभियान से सियासत गरमाई, भाजपा का डिजिटल हमला और कांग्रेस की साख पर बड़ा सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजनीति में सोशल मीडिया अब केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक रणनीति का सबसे प्रभावशाली मंच बन चुका है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ एक व्यापक और सुनियोजित डिजिटल अभियान शुरू किया है, जिसे 'कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस' नाम दिया गया है। 25 फरवरी को लॉन्च किए गए इस मेगा सोशल मीडिया अभियान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी इस अभियान के जरिए कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे हैं।

इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्राफिक्स और डिजिटल विजुअल्स का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर #CompromisedCongress हैशटैग के साथ पोस्ट साझा कर रहे हैं, जिनमें कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व की नीतियों, निर्णयों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन पोस्ट्स में एआई द्वारा निर्मित तस्वीरें, वीडियो

और ग्राफिक्स के माध्यम से एक सशक्त राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है।

इस अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर सीधा हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्य और बयान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। गोयल ने कहा कि यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक सोच का हिस्सा है जो देश के हितों के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देती है। उनके इस बयान ने इस अभियान को और अधिक चर्चा में ला दिया है और राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है।

भाजपा का यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक श्रृंखला के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को उठाकर कांग्रेस की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा का दावा है कि यह अभियान जनता को कांग्रेस के कथित 'समझौता करने वाले' रवैये के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने कई मौकों पर राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है और यह अभियान उसी सच्चाई को सामने लाने का प्रयास है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का यह अभियान आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह के अभियान का उद्देश्य युवाओं और शहरी मतदाताओं तक तेजी से पहुंच बनाना होता है, क्योंकि आज का मतदाता सोशल मीडिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश तेजी से फैलता है और इसका प्रभाव व्यापक होता है, जिससे राजनीतिक दलों को अपनी बात जनता तक पहुंचाने में आसानी होती है।

दूसरी ओर, कांग्रेस और उसके समर्थकों ने भाजपा के इस अभियान को एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया है। उनका कहना है कि भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अभियान चला रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि भाजपा सरकार को देश की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि विपक्ष के खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाने पर। यह अभियान इस बात का भी संकेत है कि भारतीय राजनीति में डिजिटल युद्ध अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। पहले जहां राजनीतिक लड़ाई केवल चुनावी सभाओं और पारंपरिक मीडिया तक सीमित थी, वहीं अब सोशल मीडिया इस लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। यहां हर पार्टी अपनी रणनीति के तहत जनता को प्रभावित करने की कोशिश करती है और अपनी छवि को मजबूत बनाने का प्रयास करती है।

भाजपा का यह अभियान इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि पार्टी तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कितनी प्रभावी तरीके से कर रही है।

आर. नल्लाकन्नू नहीं रहे, 101 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

(जीएनएस)। चेन्नई। भारतीय राजनीति और वामपंथी आंदोलन के इतिहास में एक अमिट पहचान बनाने वाले वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता आर. नल्लाकन्नू का बुधवार को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन का एक ऐसा अध्याय समाप्त हो गया, जिसने दशकों तक श्रमिकों, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वे पिछले 22 दिनों से चेन्नई स्थित राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन अंततः उम्र और बीमारी के सामने उनका शरीर जवाब दे गया और उन्होंने अंतिम सांस ली।

उनके निधन की खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, श्रमिक संघों और आम नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी और कहा कि नल्लाकन्नू केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक विचार, एक संघर्ष और एक नैतिक शक्ति थे। उन्होंने कहा कि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा और उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

नल्लाकन्नू का जीवन सादगी, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक था। वे उन दुर्लभ नेताओं में से एक थे जिन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा का एक पवित्र दायित्व माना। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में से एक थे और उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके विचार और संकल्प असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता, गरीबी और अन्याय को करीब से देखा। इन अनुभवों ने उनके मन में एक गहरी संवेदना और परिवर्तन की इच्छा पैदा की। उन्होंने युवावस्था में ही सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया और जल्द ही कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ गए। वे मानते थे कि समाज में वास्तविक बदलाव केवल संगठित संघर्ष और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अटूट ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा थी। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता नहीं दी और हमेशा जनता के हितों को सर्वोपरि रखा।

बंगाल के मतदाता सत्यापन में अब पड़ोसी राज्यों की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तेज होगी प्रक्रिया और सियासी बहस भी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद और देरी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है, जिसने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब इस प्रक्रिया में केवल पश्चिम बंगाल के न्यायिक अधिकारियों पर निर्भर रहने के बजाय झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इस निर्णय का उद्देश्य मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करना, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना और आगामी चुनावों के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं। बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों और सीमित न्यायिक संसाधनों के कारण यह प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अदालत को बताया गया कि राज्य में लगभग 50 लाख आवेदन अभी भी लंबित हैं और उपलब्ध न्यायिक अधिकारियों की संख्या इस भारी कार्यभार के मुकाबले अपर्याप्त है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत को यह जानकारी दी थी कि इस प्रक्रिया में पहले ही करीब 250 न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया है, लेकिन काम की विशालता के कारण समयसीमा के भीतर इसे पूरा करना बेहद कठिन साबित हो रहा है।

इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यावहारिक और संतुलित समाधान प्रस्तुत किया। अदालत ने आदेश दिया कि झारखंड और ओडिशा के अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि इन अधिकारियों के पास कम से कम तीन वर्षों का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, ताकि वे निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक इस जिम्मेदारी को निभा सकें। अदालत का यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक पारदर्शिता दोनों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की वैधता को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड, हाईस्कूल के एडमिट कार्ड और प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को भी वैध पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे उन लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले दस्तावेजों की अस्पष्टता या अस्वीकृति के कारण प्रक्रिया में अटके हुए थे। इसके अलावा अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 14 फरवरी से पहले जिन लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपने दस्तावेज जमा किए हैं, उनके आवेदन स्वीकार किए जाएं और उनका सत्यापन किया जाए।

इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार पहले से ही इस प्रक्रिया की जटिलता और समय की आवश्यकता को लेकर चिंता जता रही थी। उनका मानना है कि बाहरी राज्यों के न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने से प्रक्रिया में तेजी आएगी और मतदाता सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय बन सकेगी।

वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को अलग दृष्टिकोण से देखा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि दूसरे राज्यों के न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने का मतलब यह है कि राज्य की मौजूदा व्यवस्था पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सका। उनका तर्क है कि यह निर्णय राज्य सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़ा करता है और यह दर्शाता है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए स्पष्ट समयसीमा भी तय की है। अदालत ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए 28 फरवरी की अंतिम तिथि निर्धारित की है। हालांकि, अदालत ने यह भी अनुमति दी है कि यदि आवश्यक हो, तो इस तिथि के बाद पूरक सूची (Supplementary List) भी प्रकाशित की जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची इन दोनों सूचियों को मिलाकर तैयार की जाएगी, जिससे कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

इस फैसले का प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रशासनिक दृष्टि से यह निर्णय लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद करेगा और चुनाव आयोग को समय पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने में सहायता करेगा। वहीं राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला आगामी चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रणाली की सक्रियता और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अदालत ने न केवल समस्या की गंभीरता को समझा, बल्कि उसका व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत किया। इससे यह संदेश गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव है। मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही सूची लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का आधार बनती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले के बाद SIR की प्रक्रिया किस गति से आगे बढ़ती है और क्या यह निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हो पाती है। हालांकि, इतना स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने इस प्रक्रिया को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है, जिससे चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

संपादकीय

आतंक पर प्रहार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट के दौर में लगातार घातक और ग्लोबल होते आतंकवाद से निपटना देश-दुनिया की बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के चलते दुनिया का कोई कोना आज आतंकवाद से अछूता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आतंकवाद से मुकाबला करने वाला हमारा तंत्र तकनीक और संसाधनों के दृष्टिकोण से उन्नत नहीं है, जिसके चलते अपराधी पुलिस व सुरक्षा बलों पर इक्कीस पड़ते हैं। संगठित अपराधी गिरोह हवाला और अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाकर सरकारों को चुनौती देने लगे हैं। इस संकट के आलोक में भारत सरकार ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। भारत सरकार ने अब आतंकवाद के खिलाफ जंग में नई राष्ट्रीय नीति और रणनीति 'प्रहार' को सिरे चढ़ाने की घोषणा की है। 'प्रहार' अर्थात् 'प्रिवेंशन, रिस्पांस एंड हेल्थिंग अप्रोच टू एंटी-टेररिज्म।' गृह मंत्रालय द्वारा तैयार इस आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति में पहली बार डिजिटल खतरों को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही के दिनों में देश के भोले-भाले नागरिकों को जिस तरह हाउस अरेस्ट करके सरेआम लूटा गया, उससे देश के सभ्य समाज में भय व्याप्त है। लोगों की जीवनभर की जमापूंजी और सेवानिवृत्ति लोगों के पूरे सेवाकाल की बचत पर जिस तरह ऑनलाइन डाका डाला जा रहा है, उसे देखते हुए डिजिटल खतरों को आतंकवाद की श्रेणी में रखना वक्त की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि डिजिटल अपराधों से आतंक फैलाने वालों को आतंकवादियों जैसी सजा देने का प्रावधान हो। हाल ही के दिनों में देश में साइबर हमले और आपराधिक हैकिंग के मामले भी खासे बढ़े हैं। यह स्वागतयोग्य है कि नई आतंकवाद विरोधी नीति में दुनिया के काले कारोबार की कुख्यात धारा डार्क वेब, क्रिप्टो मायाजाल आदि उन्नत तकनीकों द्वारा अपराध जगत को सींचने वाले वित्तपोषक तंत्र से निपटना भी नई आतंकवाद विरोधी नीति का लक्ष्य होगा, जो आज देश में आतंकवाद पोषण का जरिया बन रहा है। निस्संदेह, हाल ही के दिनों में सीमा पार से जारी ड्रोन हमले और साइबर आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आतंकवादी हमलों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। यदि खतरे को समय रहते भांपते हुए तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके तो नागरिकों के हित सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिये जरूरी है कि नागरिक सुरक्षा में लगी पुलिस, सुरक्षा बलों तथा अन्य आंतरिक क्षमताओं को एकीकृत किया जाए। साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले संगठनों पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ जारी इस रणनीति में आतंकी हमलों की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस सूचनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, सुरक्षा बलों को उन्नत हथियार उपलब्ध कराने, नई तकनीक से लैस करने, पुलिस, एनएसजी व केंद्रीय सुरक्षा बलों में समन्वय से तत्काल प्रतिक्रिया देने, सुरक्षा एजेंसियों के आधुनिकीकरण व प्रशिक्षण से आतंक पर प्रहार की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहली बार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भी आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे में शामिल किया गया है। इसके अलावा समाज में कट्टरपंथ को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का जिक्र आतंकवाद विरोधी नीति में शामिल है, जिसमें सामुदायिक नेताओं, धर्मगुरु व स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी ली जाएगी। निस्संदेह, समय के साथ बढ़ती आतंकवाद की चुनौती के मुकाबले में नागरिकों की सजगता व सतर्कता एक बड़ी भूमिका हो सकती है। वहीं दूसरी ओर नई आतंकवाद विरोधी नीति में समग्र सामाजिक प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें आतंकी हमलों के बाद समुदाय को एकीकृत करने, मनोवैज्ञानिकों, अधिवक्ताओं तथा समाजसेवी संगठनों की मदद से स्थिति सामान्य करने में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। लेकिन यहां यह भी जरूरी है कि आतंकवाद के खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और कानून व्यवस्था पर आधारित प्रतिक्रिया दी जाए। निस्संदेह, लगातार मारक होती आतंकवाद की चुनौती के मुकाबले के लिए समग्र नीति के साथ नागरिकों की सजगता व सतर्कता भी बेहद जरूरी है।

संज्ञानात्मक युद्ध : दांवपेच का सातवां रणक्षेत्र

> “ मेघना नदी दस्तावेज की तार्किक सीख है कि भारत का संवैधानिक प्रारूप एक राजनीतिक विकल्प से कहीं अधिक है। यह संज्ञानात्मक लचीलेपन के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृत्रिम नैरेटिव के युग में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक परम 'वितरित रक्षा' के रूप में कार्य करती है।

युद्ध का शब्दिक अर्थ अपनी परिभाषा से बाहर निकल चुका है। सदियों से, शक्ति का माप हल की नोक और युद्धपोत के पीछे बनने वाली लहरों से किया जाता रहा है। रणनीति ने भूमि, समुद्र, वायु, शांत गहराइयों, अंतरिक्ष के निर्वात और साइबर ग्रिड की टिमटिमाती शिराओं का मानचित्रण कर लिया है। आज एक सातवें कार्यक्षेत्र (डोमेन) ने चुपचाप रणनीति की धुरी को हर लिया है। एक अनुभूति : सबसे अंतरंग और सबसे व्यापक।

यह बदलाव अब और अधिक सैद्धांतिक नहीं रहा। पूर्वी यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया तक और हमारी अपनी विवादित सीमाओं पर, युद्ध का दायरा पहले ही विस्तृत हो चुका है। प्रभाव अभियान अब प्रत्यक्ष कार्रवाई से पहले, उसके साथ और उसके बाद तक जारी रहता है। केंद्र बिंदु अब मंचों से धारणा की तरफ सरक रहा है, केवल मारक क्षमता से हटकर एकजुटता कायम रखने वाला समाज ही तनाव के दौरान बचा रह सकता है।

आधुनिक युद्धक्षेत्रों में, नैरेटिव की गति, सूचनागत आघात और सामाजिक लचीलेपन के जरिए परिणाम निरंतर आकार लेते जा रहे हैं। धारणा ने अब ओओडीए लूप्स, एस्केलेशन थ्रेशोल्ड और राजनीतिक निर्णय चक्रों को इस प्रकार संकुचित कर दिया है, जिसका अनुमान परंपरागत सिद्धांत पूरी तरह लगा नहीं पाए।

एकजुट रखने वाला कार्यक्षेत्र : राष्ट्र शक्ति का शून्य-

शून्य, भारतीय सभ्यता का एक योगदान, गणित में वह मूक गुणांक है जो पैमाना बनाता है। किसी राष्ट्र की संरचना में सामाजिक सामंजस्य वही बुनियादी भूमिका निभाता है। इस शून्य के बिना, शक्ति का अंकगणित अस्थिर हो जाता है। इसके बगैर, सबसे उन्नत गतिज ताकतें, मिसाइलें, उपग्रह और विमान वाहक बेड़े तक भी आकर्षण खो देते हैं। जब सामाजिक विश्वास भंग हो जाए, तो सैन्य क्षमता थम जाती है। जब दोनों एकीकृत हो जाएं, तो राष्ट्रीय शक्ति अधिक वेग से आगे बढ़ती है। इसलिए संज्ञान आधुनिक युद्धों में जोड़ने वाले डोमेन के रूप में उभरा है। इसकी एक सतह पर लोगों में एकता निहित है; दूसरी सतह पर युद्ध के छह पारंपरिक माध्यम संचालित होते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, लेकिन उनकी असली क्षमता एकीकरण में निहित है। सातवें कार्यक्षेत्र में एकता वह जोड़ने वाला पदार्थ है जो सबको थामे रखता है।

नदी का सिद्धांत : क्षरण से घेराबंदी तक - भारत ने 1971 के युद्ध में इस गतिशीलता का आरंभिक प्रदर्शन देख लिया था। 'मेघना क्रॉसिंग', एक दुस्साहसिक नदी पारीय अभियान, जिसने ढाका के लिए राह खोल दी, इसने बलों की तैनाती से कहीं अधिक किया। इसने प्रतिद्वंद्वी की अपरिहार्यता की धारणा को बदलकर रख दिया।

जलीय बाधा के तर्क ने आगे बढ़ने की संभावना को खारिज कर रखा था, लेकिन वायुसैन्य प्रहारों और बख्तरबंद दस्तों वाले अभियान ने संज्ञानात्मक अनुभूति आघात दिया। प्रतिद्वंद्वी के पास गोला-बारूद ख़त्म नहीं हुआ था; बल्कि लड़ने की इच्छाशक्ति उखड़ गई थी। इस संज्ञानात्मक आघात ने आत्मसमर्पण गति को तीव्रता दी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, 'मेघना सिद्धांत' पुनः तीव्र प्रासंगिकता प्राप्त कर गया है। सातवें डोमेन में, उद्देश्य संज्ञानात्मक घेराबंदी बनाना हैः प्रतिद्वंद्वी द्वारा भंग करने से कहीं पहले, अपने प्रणालीगत संतुलन की संभाल लेना। यह लाभ संकट के दौरान कभी भी सुधारा नहीं जा सकता; इसे युद्धों के बीच के काल में निरंतर, कल्पनाशील प्रशिक्षण के माध्यम से ढालना पड़ता है।

भारत की संरचनात्मक उत्कृष्ट कृति : वितरित लचीलापन : अधिकांश आधुनिक शक्तियां किले जैसी हैं, केंद्रीकृत, भव्य, और अक्सर भंगुर। भारत अलग ढंग से विकसित हुआ है। यह एक जीवंत नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। संविधान की प्रस्तावना सोर्स कोड के रूप में कार्य करती है। बहुलवाद उच्च स्तरीय झटका-अवशोषक के रूप में कार्य करता है। 'अनेकता में एकता' महज बयानबाजी के रूप में नहीं बल्कि वितरित रक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करती है।

चुनावी मंथन, भाषाई बहुलता और संघीय जटिलता गणतंत्र पर बार-बार दबाव डालकर इसका इम्तिहान लेती है। रणनीतिक गहराई उस संचित अनुभव से बनी है। 1.4 अरब अलग-अलग स्वरों का एक देश, जो लोकतांत्रिक सहमति से जुड़ा हुआ है, वह सूचनात्मक झटकों का असामान्य रूप से शक्तिशाली अवशोषक बन जाता है। वह शक्ति जो सामाजिक रूप से स्थिर नहीं होती, वह रणनीतिक रूप से नाजुक हो जाती है। 1962 के बाद का हर युद्ध इस सहनशक्ति का गवाह है।

एआई का दौर और डिजिटल ढांचा : कृत्रिम बुद्धिमत्ता धारणा और प्रतिक्रिया के बीच अंतराल को कम कर रही है। ऐसे माहौल में विश्वसनीयता खुद-ब-खुद युद्धक शक्ति का एक रूप बन जाती है। ड्रोन एक हवाई मशीन है, संज्ञान माध्यम है। भारत का डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ढांचा जनता के स्तर पर विश्वास निर्माण हेतु पहले से बना बनाया सांचा प्रदान करता है। सही ढंग से संचालित, ऐसे मंच सुनिश्चित कर सकते हैं कि धारणा और सत्यापन योग्य वास्तविकता के बीच अंतर खतरनाक रूप से न बढ़ने पाए।

यूक्रेन - एक तनाव परीक्षा : यूक्रेन-रूस संघर्ष सातवें डोमेन का तनाव के दौरान गहराई से परीक्षा का अवसर प्रदान करता है। सालों से जारी युद्ध में, अकेले युद्धक्षेत्र प्रदर्शन ने रणनीतिक सहनशीलता का निर्धारण नहीं किया है। नैरेटिव सुसंगतता, आर्थिक सहनशक्ति और राजनीतिक वैधता परंपरा को जारी रखे हुए है।

जो चीज़ लगातार दिखाई दे रही है, वह है लंबे समय से तनाव के बीच भी सामाजिक एकता की धुरी कायम रहना। जो राष्ट्र आंतरिक विश्वास बनाए रखेंगे, वे उद्देश्य पर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं; जहां पर परस्पर भरोसा खंडित हो जाए, वहां पर रणनीतिक हानि जमा होती जाती है।

अपने स्थापना काल से ही, भारत ने 'वी द पीपल' (हम लोग) को मूल में रखा है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नागरिक समरसता को क्रियान्वित किया है। सातवें डोमेन में, सहनशक्ति का प्रवाह न केवल मारक क्षमता से बनता है, बल्कि इसके पीछे मौजूद एकजुटता से तैयार होता है।

लंबे युद्ध की हकीकत : आधुनिक संघर्ष एक गतिज कृत्य होने के बजाए लंबे खिंचने वाले प्रणालीगत द्वंद्व में बदल चुका है। विस्तारित लड़ाइयों में, जो पक्ष सीखने के चक्र में महारत हासिल कर लेता है वह दिशा निर्धारित करता है, लेकिन सहनशक्ति उसी देश में प्रवाहित होगी, जो अपने नैतिक एवं संस्थागत आधार को संरक्षित रख पाएगा।

जीत अब एकमात्र सफलता नहीं रह गई है। समय और दूरी से परे, यह निर्णयगत लाभ को सतत रखना हो गया। कथात्मक प्रचार शिथिलता, निर्णय अधिभार, और संस्थागत फिसलन अब रणक्षेत्र में नुकसान की भांति हैं।

खुद सिद्धांत को अनुकूलन के लिए निरंतर मजबूर किया जा रहा है। रियल टाइम में क्रमिक विकास करने वाले संघर्षों में गैर-लचीली संहिता हाथ-पैर मारती रह जाती है। आधुनिक युद्धक्षेत्र उन संगठनों को पुरस्कृत करता है जो निरंतर सीखेंगे, बुद्धिमानी से विकेंद्रीकरण कर सकेंगे, और एकता खोए बगैर खुद को बदल सकते हैं। यहां फिर से, गहरा लाभ उन सामाजिक एवं संवैधानिक आधारों में निहित है जो दबाव के बावजूद स्पष्टता बनाए रखते हैं।

अंततः समरूपता : आखिरकार, सातवां डोमेन किसी राष्ट्र की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। कृत्रिम नैरेटिव्स और कृत्रिम प्रचार के युग में, लाभ उस समाज को होगा जो निरंतर तनाव के बीच एकजुटता कायम रखेगा। मशीन की अराजकता के विरुद्ध सबसे मजबूत बचाव 'हम लोग' की सतत सुस्पष्टता है। संज्ञान युग में, एकता स्वयं ही निवारण बन जाती है, और प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय लचीलेपन में एक हितधारक होता है। युद्धों को अब लड़ने से पहले ही आकार दिया जाता है। यदि लड़ाई हम पर थोपी जाती है, तो जो राष्ट्र अपने डोमेन (कार्यक्षेत्र) को स्पष्टता और एकजुटता के साथ संरेखित रख पाएगा, वह न केवल बल के जरिए बल्कि प्रणालीगत लाभ के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करेगा।

सातवें डोमेन में, जीत पहली गोली चलाने से काफी पहले शुरू हो जाती है और आखिरी गोली थमने के काफी देर बाद तक कायम रहती है।

प्रेरणा

सेवा का मौन रहस्य: जब झुकना ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है

मानव जीवन में सेवा का स्थान अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। सेवा केवल किसी की सहायता करने का कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी पहचान की इच्छा के सेवा करता है, तब वह अपने भीतर के उस मौन सत्य को छूता है, जो शब्दों से परे है।

अहंकार मनुष्य के भीतर एक अदृश्य भार की तरह होता है। यह भार उसे हमेशा ऊपर उठने से रोकता है। यह उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह स्वयं ही सब कुछ है, कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मनुष्य सेवा करता है, तब यह भार धीरे-धीरे हल्का होने लगता है। सेवा मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि वह अकेला नहीं है, कि वह एक व्यापक चेतना का हिस्सा है।

विनम्रता सेवा की आत्मा है। बिना विनम्रता के सेवा केवल एक क्रिया बन जाती है, जिसमें आत्मा का कोई स्पर्श नहीं होता। लेकिन जब सेवा विनम्रता से की जाती है, तब वह साधना बन जाती है। तब वह मनुष्य को भीतर से बदलने लगती है।

जब कोई व्यक्ति झुककर किसी छोटे कार्य को करता है, तब वह केवल उस कार्य को पूरा नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर के अहंकार को भी कम कर रहा होता है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है।

मनुष्य का अहंकार उसे हमेशा ऊपर खड़ा रहने के लिए प्रेरित करता है। यह उसे झुकने से रोकता है। लेकिन आध्यात्मिकता का मार्ग झुकने से ही शुरू होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य झुकता नहीं है, तब तक वह सीख नहीं सकता। और जब तक वह सीख नहीं सकता, तब तक वह विकसित नहीं हो सकता।

सेवा मनुष्य को यह सिखाती है कि वास्तविक शक्ति क्या है। वास्तविक शक्ति दूसरों पर नियंत्रण करने में नहीं होती, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण करने में होती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेता है, तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है।

सेवा का एक और गहरा प्रभाव यह है कि यह मनुष्य के भीतर प्रेम को जागृत करती है। जब मनुष्य सेवा करता है, तब वह दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है। वह दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगता है। यह अनुभव उसे भीतर से बदल देता है।

धीरे-धीरे वह यह समझने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। यही समझ उसे ईश्वर के निकट ले जाती है।

सेवा का मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। क्योंकि यह मार्ग मनुष्य को अपने अहंकार का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है।

और जब मनुष्य इस मार्ग पर चलता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं हैं। वे उसी क्षण उसके भीतर प्रकट होते हैं, जब वह स्वयं को भूलकर दूसरों की सेवा करता है।

हेक्सागन गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मायने समझिए

इजरायल द्वारा प्रस्तावित "हेक्सागन गठबंधन" के अंतर्राष्ट्रीय मायने बेहद दिलचस्प हैं। यह अतिवादी ताकतों के विरूद्ध शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित यह गठबंधन एक ऐसा कूटनीतिक समूह है, जिसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी राष्ट्र, ग्रीस, साइप्रस और अन्य एशियाई देश शामिल होंगे। समझा जाता है कि भले ही इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य कट्टरपंथी शिया और सुन्नी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके उन वैश्विक कूटनीतिक निहितार्थों से भी इंकार नहीं किया जा सकता, जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे तीनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के कान खड़े करने वाले साबित हो सकते हैं।

ऐसा इसलिए कि इस गठबंधन में विश्व की चौथी बड़ी शक्ति भारत बेहद मजबूत और नेतृत्वकारी स्थिति में रहेगा। लिहाजा इसका स्वरूप तय हो जाने के बाद अरब और खाड़ी के इस्लामिक देशों पर वर्चस्व की जो होड़ वैश्विक महाशक्तियों के बीच मची रहती है, उस पर एक हद तक अल्पविराम भी लगेगा।

दरअसल, हेक्सागन गठबंधन छह-पक्षीय (हेक्सागन) धुरी है जो पश्चिम एशिया में नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगी, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप से भी इसे पूरी ताकत मिलेगी। यह भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) से भी जुड़ी हुई है।

वहीं इस बेमिसाल गठबंधन में भारत को प्रमुख भूमिका दी गई है, जिसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुरक्षा सहयोग पर फोकस होगा। जहां तक भारत की भागीदारी की बात है तो भारत अभी आधिकारिक रूप से इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी की 25-26 फरवरी 2026 को होने वाली इजरायल यात्रा के दौरान इस पर चर्चा और समझौते होने की संभावना बलवती है।

समझा जाता है कि यह 2017 के बाद पीएम मोदी की यह दूसरी बड़ी यात्रा होगी, जो पारस्परिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी। वहीं नेतन्याहू ने इसे कट्टरपंथ विरोधी नई धुरी बताया है। उल्लेखनीय है कि हेक्सागन गठबंधन अभी औपचारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आया है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले प्रमुख देशों या समूहों में इजरायल, भारत, ग्रीस, साइप्रस, कुछ अरब राष्ट्र और अफ्रीकी देश शामिल बताए गए हैं। इस गठबंधन का मुख्य देश इजरायल है जो गठबंधन का प्रस्तावक और केंद्र बिंदु है। जबकि भारत इसके प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जा रहा है, खासकर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के लिए। वहीं ग्रीस और साइप्रस इसके भूमध्यसागरीय रणनीतिक साझेदार देश हैं। जबकि अरब के कतिपय देश विकास और शांति समर्थक राष्ट्र के तौर पर रहेंगे। वहीं अफ्रीकी देश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसमें शामिल होंगे। जबकि अन्य एशियाई देश इसमें भारत और उस जैसे सहयोगी की भूमिका में शामिल किए जाएंगे। जहां तक हेक्सागन गठबंधन के उद्देश्य की बात है तो यह गठबंधन कट्टरपंथी शिया-सुन्नी ताकतों के खिलाफ एकजुटता का प्रयास है, जिसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे से जुड़ाव हो सकता है। वहीं इसका मुख्य ध्येय कट्टरपंथी शिया और सुन्नी ताकतों (जैसे ईरान समर्थित शिया धुरी और उभरती सुन्नी कट्टरपंथी शक्तियों) के खिलाफ एकजुट होकर क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है।

यह गठबंधन भूमध्य सागर, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के सहयोगी देशों को एक मंच पर लाकर कट्टरपंथ, आतंकवाद और अस्थिरता का सामना करने का एक सशक्त प्रयास है। इसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को मजबूत करना, AI, क्वांटम तकनीक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

देखा जाए तो हेक्सागन गठबंधन की भावी योजनाओं से चीन के BRI जैसे प्रयासों को चुनौती मिल सकती है। इसका अपेक्षित प्रभाव यह होगा कि एक 'नई वैश्विक धुरी' बनाने का जो नेतन्याहू का विजन है, वो विकास-समर्थक राष्ट्रों को शांति और समृद्धि के लिए एकजुट करने वाला है। इसलिए भारत इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

यही वजह है कि हेक्सागन गठबंधन से भारत को वैश्विक महाशक्ति के केंद्र के रूप में उभरने में रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी लाभ मिलेंगे। क्योंकि यह 'नया नाटो' जैसा समूह भारत को मध्य पूर्व-यूरोप तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करेगा। लिहाजा, इस नई स्थिति का प्रमुख लाभ रणनीतिक ऊंचाई प्राप्त करना है।

इससे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में भारत की गिनती बढ़ेगी, और कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनेगा। यह इसलिए भी जरूरी है कि अमेरिका-चीन जैसे अहम वैश्विक खिलाड़ी अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद के द्वंद्व में उलझे हुए हैं।

जहां तक भारत की आर्थिक पहुंच की बात है तो IMEC गलियारे से मिडिल ईस्ट-यूरोप तक सीधा सुरक्षित मार्ग मिलेगा, जो चीन के BRI को चुनौती देता हुआ प्रतीत होगा।वहीं भारत को तकनीकी सहयोग मिलेगा। खासकर AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस (मिसाइल, ड्रोन) और सुरक्षा साझेदारी मजबूत होगी।

इसका क्षेत्रीय प्रभाव यह पड़ेगा कि अरब-अफ्रीकी देशों से भारत के संबंध मजबूत होंगे, और अमेरिका के बिना भी भारत का स्वतंत्र सुरक्षा तंत्र मजबूत बना रहेगा। वहीं अपेक्षित प्रभाव यह होगा कि पीएम मोदी की इजरायल यात्रा से ये सभी लाभ औपचारिक हो सकते हैं, जो भारत को वैश्विक पावर बैलेंस में मजबूत बनाएंगे।

सच कहूं तो हेक्सागन गठबंधन चीन के लिए चुनौती है क्योंकि यह चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' (BRI) प्रोजेक्ट को सीधे चुनौती देगा। खासकर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) को मजबूत कर यह वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाएगा। इसका प्रमुख कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा है।

अभियान

फाल्गुन का ब्रह्मांडीय रहस्य: जब चंद्र चेतना, तंत्र शक्ति और आत्मा का मिलन होता है

सनातन धर्म में समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं मापा जाता, बल्कि चेतना की तरंगों से मापा जाता है। हिंदू पंचांग की रचना इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें महीनों का निर्धारण सूर्य के नहीं, बल्कि चंद्रमा और नक्षत्रों के आधार पर किया गया है। यह व्यवस्था केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय विज्ञान का एक सूक्ष्म और गहरा रूप है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, उसी के आधार पर उस महीने का नाम रखा जाता है। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित होता है, तब उस महीने को फाल्गुन कहा जाता है।

यह केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा का संकेत है, जो इस समय पृथ्वी और मानव चेतना पर सक्रिय होती है। चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में मन का स्वामी माना गया है। मन ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा आत्मा संसार का अनुभव करती है। जब चंद्रमा की स्थिति बदलती है, तब मन की स्थिति भी बदलती है। यही कारण है कि फाल्गुन का महीना मन और आत्मा के संतुलन का महीना माना जाता है।

प्राचीन शास्त्र पद्मपुराण में उल्लेख मिलता है कि यह महीना चंद्रदेव की ऊर्जा के जागरण का काल है। इसका अर्थ यह है कि इस समय मन की सुप्त शक्तियां जाग्रत होने लगती हैं। व्यक्ति अपने भीतर एक नई संवेदनशीलता, एक नई स्पष्टता और एक नई चेतना का अनुभव करता है।

तांत्रिक दृष्टि से यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तंत्र शास्त्र में चंद्रमा को शक्ति का स्रोत माना गया है। सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। जब मन और आत्मा के बीच संतुलन होता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है।

फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह वह रात होती है, जब चंद्रमा सूर्य के सबसे निकट होता है। यह स्थिति एक गहरे आध्यात्मिक प्रतीक को दर्शाती है। चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है। जब मन आत्मा के निकट होता है, तब व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है।

इसी कारण इस दिन भगवान भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वह चेतना का प्रतीक हैं। वह वह अवस्था हैं, जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है।

जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर की उस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है, जो सामान्य अवस्था में छिपी रहती है।

फाल्गुन का महीना प्रकृति के परिवर्तन का भी समय है। यह वह समय है, जब सर्दी समाप्त होती है और वसंत का आगमन होता है। यह बाहरी परिवर्तन वास्तव में आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे प्रकृति पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्तों को धारण करती है, वैसे ही व्यक्ति भी अपने पुराने विचारों और भावनाओं को छोड़कर नई चेतना को अपनाता है।

इस महीने में चंद्रदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। जब व्यक्ति दुग्ध मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य देता है, तब यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा संबंधी प्रक्रिया होती है। दूध शुद्धता का प्रतीक है और जल प्रवाह का प्रतीक है। जब इन दोनों को मिलाकर चंद्रमा को अर्पित किया जाता है, तब यह मन की शुद्धि और संतुलन का प्रतीक बन जाता है।

वैदिक परंपरा में यह भी माना जाता है कि इस महीने में भगवान भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से प्रेम और चेतना का विकास होता है। श्रीकृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि वह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक हैं। जब व्यक्ति प्रेम की अवस्था में होता है, तब उसका मन शांत होता है और वह ईश्वर के निकट होता है।

इसी प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा इस महीने में विशेष फलदायी मानी जाती है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, बल्कि वह संतुलन और समृद्धि की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब व्यक्ति संतुलित होता है, तब उसके जीवन में समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है।

तंत्र शास्त्र के अनुसार फाल्गुन की पूर्णिमा को ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह समय होता है, जब व्यक्ति ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जाग्रत कर सकता है। मानव शरीर में कई ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब चंद्रमा की ऊर्जा इन चक्रों को प्रभावित करती है, तब व्यक्ति अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करता है।

धीरे-धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। उसके विचार स्पष्ट होने लगते हैं। वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है।

यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि यह धीरे-धीरे होता है। जैसे चंद्रमा धीरे-धीरे पूर्ण होता है, वैसे ही व्यक्ति की चेतना भी धीरे-धीरे पूर्ण होती है। फाल्गुन का महीना व्यक्ति को यह अवसर देता है कि वह अपने भीतर झांके। वह अपने मन को समझे। वह अपनी भावनाओं को पहचाने।

जब व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, तब वह अपने जीवन को समझ लेता है।

और जब वह अपने जीवन को समझ लेता है, तब वह अपने अस्तित्व को समझ लेता है।

फाल्गुन का वास्तविक रहस्य यही है कि यह व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाता है।

यह उसे यह अनुभव कराता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वह एक चेतना है।

और जब यह अनुभव होता है, तब व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तब उसे बाहरी चीजों में सुख खोजने की आवश्यकता नहीं होती। तब वह अपने भीतर ही उस सुख को अनुभव करता है।

तब उसे यह अनुभव होता है कि ब्रह्मांड और वह अलग नहीं हैं। वे एक ही हैं।

और यही फाल्गुन का सबसे बड़ा रहस्य है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात के शहरों में स्वदेशी मलों के आयोजन से 'वोकल फॉर लोकल' को प्रोत्साहन

▸▸ गुजरात शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत 15 मार्च तक 152 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे

▸▸ अब तक 38 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों का प्रारंभ, 1 लाख से अधिक लोग पहुँचे, 83 लाख से अधिक की बिक्री हुई

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र का अनुकरण करते हुए देश के नागरिकों का स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी कारीगरों, हस्तकलाकारों तथा छोटे उद्योगों को समर्थन देने के लिए अनेक नई पहलें की हैं। 'गुजरात आत्मनिर्भर यात्रा', 'जी-मैत्री योजना', 'महिला उद्योग सहायता योजना' जैसे कार्यक्रमों द्वारा राज्य में स्वदेशी उत्पादों को नई ऊर्जा मिल रही है। इसके अतिरिक्त; शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग अंतर्गत गुजरात शहरी आजीविका मिशन द्वारा स्वदेशी मेलों (शॉपिंग फेस्टिवल) का राज्यव्यापी आयोजन किया जा रहा है; जिनके माध्यम से स्थानीय कारीगरों, स्वयंसहायता समूहों तथा छोटे व्यापारियों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष दशहरा से दीपावली के दौरान राज्य के 16 शहरों में प्लास्टिक फ्री 'स्वदेशी फेस्टिवल' का सफल आयोजन किया गया था। इन मेलों में 40.50 लाख से अधिक लोग आए थे और 10 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री दर्ज हुई थी। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के सभी नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों (शॉपिंग फेस्टिवल) का आयोजन

किया गया है; जिनके द्वारा स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी), स्थानीय कारीगरों, कलाकारों तथा छोटे व्यापारियों को अपने स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित करने व बेचने का उत्तम अवसर मिलेगा।

15 मार्च तक राज्य के 152 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेले आयोजित होंगे

15 मार्च, 2026 तक राज्य के सभी 152 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के तहत 1500 से अधिक स्टॉल स्वयंसहायता समूहों को आवंटित किए गए हैं, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स को 1400 से अधिक स्टॉल दिए गए हैं। खान-पान के 1500 स्टॉल तैयार किए जा रहे हैं और अन्य कारीगरों को अपने स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने के लिए 1650 से अधिक स्टॉल आवंटित किए गए हैं।

अब तक 38 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों का प्रारंभ, 83 लाख रुपए से अधिक की बिक्री

राज्य में अब तक 38 नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेले शुरू किए गए हैं; जिनमें अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर, राजकोट, सूरत तथा वडोदरा अंचलों के विभिन्न नगर पालिका क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोग स्वदेशी मेलों में पहुँचे और 83 लाख रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री हुई है। यह सफलता दर्शाती है कि नागरिक 'वोकल फॉर लोकल' पहल के साथ उत्साहपूर्वक जुड़ रहे हैं। स्वदेशी मेले केवल व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास हैं।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि स्वदेशी तथा आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के निर्माण का राजमार्ग है। इसका अनुकरण करते हुए गुजरात सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि आगामी समय में देश का प्रत्येक नागरिक 'वोकल फॉर लोकल' का वाहक बने और स्वदेशी के मंत्र का अनुकरण करे।

गुजरात 1 मार्च, 2026 को महात्मा मंदिर में तीसरी सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा

▸▸ सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण में वैश्विक सीईओ और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे

▸▸ माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी सेमी, केन्स और उनके वैश्विक भागीदार गुजरात के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में शामिल होंगे ' '

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार आगामी 1 मार्च, 2026 को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन (जीएसईएम) की ओर से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के आह्वान ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को भारत के ग्रोथ एजेंडा के केंद्र में स्थापित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया की उपस्थिति में इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे।

इस कॉन्फ्रेंस की थीम 'गुजरात : इंडियाज गेटवे टू सिलिकॉन' (गुजरात : सिलिकॉन के लिए भारत का प्रवेशद्वार) है, जो भारत की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के प्रमुख केंद्र के तौर पर स्थापित होने की राज्य की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है। गुजरात अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेशक-अनुकूल नीतियों के साथ, भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च क्षमताओं को गति देने में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह कॉन्फ्रेंस वैश्विक सेमीकंडक्टर सीईओ, नीति निर्माताओं और उद्योग अग्रणियों को एक साथ लाएगी, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के तहत मुख्य भाषण, थीमैटिक पैनल्स और अंतरराष्ट्रीय राउंडटेबल का आयोजन किया गया है। पहले दिन नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग, धोलेरा और साणंद जैसे हब के लिए लॉजिस्टिक्स और निर्यात की तैयारी, भविष्य के कौशल के लिए कार्यबल का विकास जैसे सत्र आयोजित किए जाएंगे। सत्रों के दौरान होने वाली चर्चाओं में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आधार को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेकर रेजिलिएंट कंपोनेंट इकोसिस्टम शामिल हैं। समानांतर सत्रों में माइक्रोन सप्लायर्स राउंडटेबल, जापान और ताइवान के साथ कंट्री-स्पेसिफिक राउंडटेबल और 'फ्रॉम सिलिकॉन टू स्टूडेंट्स : बिल्डिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर फ्यूचर' (सिलिकॉन से विद्यार्थियों तक : भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य का निर्माण) शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा और आउटरिच पर एक सेमीनार का आयोजन होगा।

दूसरे दिन, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन-एसआईआर) में गाइडेड टूर का आयोजन किया गया है, जो जीएसईएम, डीआईसीडीएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आयोजित होगा। इस गाइडेड टूर से प्रतिनिधियों को गुजरात के महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्वयं देखने का अवसर मिलेगा।

इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जिनमें टीईपीएल के सीईओ और एमडी डॉ. रणधीर ठाकुर, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा, सीजी सेमी के चेयरमैन श्री जी.सी. चतुर्वेदी, केन्स टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री रमेश कुन्हीकन्नन, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मैटेरियल्स इंटरनेशनल (सेमी) के सीईओ श्री अजित मनोचा और जॉर्जिया टेक के एमेरिटस प्रोफेसर डॉ. राव तुम्माला शामिल हैं। उनकी उपस्थिति गुजरात के सेमीकंडक्टर विजन में दुनिया के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। यह भारत को उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडर बनाने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस पहल को माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और केन्स सेमीकॉन जैसी जानीमानी सेमीकंडक्टर कंपनियों तथा जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो-जापान), कोरिया व्यापार-निवेश संवर्धन एजेंसी (कोटरा-कोरिया), इन्वेस्ट इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमी, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए), इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (ईएलसीआईएनए), इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) और मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एमईडीईपीसी) जैसे नॉलेज पार्टनर्स का समर्थन मिला है। उनकी भागीदारी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं राष्ट्रीय प्रगति को दर्शाती है।

गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के विकास की आधारशिला रखेगा। यह कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रधानमंत्री के विजन और गुजरात को नवाचार एवं निवेश का केंद्र बनाने की मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह दिखाता है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम ('गुजरात : इंडियाज गेटवे टू सिलिकॉन') से पता चलता है कि गुजरात वैश्विक चिप निर्माताओं के साथ ही स्थानीय उद्योगों, उद्यमियों एवं विद्यार्थियों का इस परिवर्तनकारी समय में योगदान देने के लिए स्वागत करता है।

वडनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण: मंडल रेल प्रबंधक ने यात्री सुविधाओं एवं नई लाइन परियोजना की प्रगति की समीक्षा

(जीएनएस)। मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने दिनांक 25.02.2026 को वडनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिले रूम, रूट रिले इंटरलॉकिंग (RRI), मास्टर केबिन, बुकिंग काउंटर, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म एवं कैफेटेरिया सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि वडनगर स्टेशन पर रेल डिब्बों में पानी भरने हेतु कोच वाटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने से ट्रेनों में वडनगर स्टेशन से ही पानी भरा जा सकेगा, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की तथा स्टेशन के समीप स्थित रेलवे क्रॉसिंग को चौड़ा करने की उनकी मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर महेसाणा–वरेठा सेक्शन के वरेठा रेलवे स्टेशन पर अंबाजी नई लाइन परियोजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कार्य के सफल समापन की जानकारी दी गई। यह कार्य आबूरोड–तारंगा हिल नई लाइन रेलखंड की भविष्य की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरेठा स्टेशन पर मुख्य लाइन पर स्थित पुराने डेड एंड ट्रैक को हटाकर नई एलाइनमेंट पर स्थानांतरित

किया गया तथा उसे नई बिछाई गई लाइन से जोड़ा गया। संशोधित यार्ड लेआउट के अनुसार नई डेड एंड लाइन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे भविष्य में तारंगा हिल दिशा में मुख्य लाइन विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह समस्त कार्य दो दिवसीय ब्लॉक के दौरान सुरक्षित एवं योजनाबद्ध तरीके से संपन्न किया गया। इस दौरान रेल कटिंग, डेड एंड ट्रैक हटाना एवं शिफ्टिंग, नई लाइन से लिंकिंग, ग्लूड जॉइंट निर्माण, वेल्डिंग, बैलेस्टिंग, पैकिंग, क्रॉसओवर की मशीन टैम्पिंग तथा अन्य आवश्यक ट्रैक समायोजन कार्य किए गए। विद्युत (TRD) विभाग द्वारा ओएचई वायरिंग हटाने एवं पुनः वायरिंग, एटीडी शिफ्टिंग/कटिंग, बॉन्डिंग कार्य तथा टॉवर वैगन से निरीक्षण किया गया। टर्नआउट क्षेत्र क्लियर होने के पश्चात सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T) विभाग द्वारा प्वाइंट परीक्षण, पुनः संयोजन एवं कमीशनिंग कार्य प्रगति पर है।

इस परियोजना से भविष्य में आबूरोड–तारंगा हिल रेलखंड की सुदृढ़ कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं अधिक सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध होगी। साथ ही अंबाजी एवं तारंगा हिल क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय व्यापार एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। बेहतर यार्ड संरचना एवं तकनीकी उन्नयन से ट्रेनों के संचालन में सुगमता आएगी तथा समयपालन में भी सुधार होगा।

लाखाबावल स्टेशन पर भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज अस्थायी रूप से रद्द

(जीएनएस)। राजकोट मंडल के अंतर्गत आने वाले लाखाबावल रेलवे स्टेशन पर नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) के निर्माण कार्य के चलते यात्री सुरक्षा एवं कार्य की सुचारु प्रगति सुनिश्चित करने हेतु ट्रेन संख्या 19209/19210 भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस का स्टॉपेज अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लाखाबावल स्टेशन पर उक्त ट्रेन का ठहराव दिनांक 26 फरवरी, 2026 से 5 मार्च, 2026 तक रद्द रहेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत ट्रेन का नियमित स्टॉपेज पुनः बहाल कर दिया जाएगा। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस अस्थायी फेरबदल को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम एवं अद्यतन जानकारी के लिए यात्री कृपया भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

पश्चिम रेलवे चलायेगी अहमदाबाद और मंगलुरु के बीच स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे होली फेस्टिवल के दौरान यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद और मंगलुरु स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09424/09423 अहमदाबाद – मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल [8 फेरे]

ट्रेन संख्या 09424 अहमदाबाद-मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल 27 फरवरी और 06,13,20 मार्च 2026 (शुक्रवार) को अहमदाबाद से 16.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20.00 बजे मंगलुरु पहुँचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09423 मंगलुरु-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल 28 फरवरी और 07,14,21 मार्च 2026 (शनिवार) को मंगलुरु से 22.30 बजे प्रस्थान करेगी और सोमवार को 02.15 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड,भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, सावर्डा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंन्दापुरा, उडुपि, मुल्की और सुरतकल स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09424 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

चीन के रेस्तरां में कोबरा-क्वीन सांप के व्यंजन वायरल हो रहे हैं, 180 डॉलर का किंग कोबरा व्यंजन खबरों में छाया हुआ है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। चीन में कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पका हुआ चिकन, मटन और कीड़े-मकोड़े परोसे जाते हैं। लेकिन एक अनोखा रेस्टोरेंट, जो लंबे समय से चल रहा है, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक ट्रैवल ब्लॉगर द्वारा बनाए गए वीडियो ने लोगों में जिज्ञासा जगा दी है। इस रेस्टोरेंट के मेनू में सांप के कई व्यंजन हैं, जिनमें किंग कोबरा भी शामिल है। यह रेस्टोरेंट एक महिला चलाती है, जिसे स्थानीय लोग कोबरा क्वीन कहते हैं। बाहर से देखने पर यह रेस्टोरेंट एक साधारण ढाबे जैसा लगता है, लेकिन यहाँ लकड़ी के बक्सों में जीवित सांप रखे जाते

हैं। ग्राहक इन लकड़ी के बक्सों में से अपनी पसंद का सांप चुनकर खा सकते हैं।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

फिर सांप को तलकर कुरकुरे चिप्स की तरह परोसा जाता है या उबालकर सूप या सब्जी के रूप में परोसा जाता है। व्यंजन की कीमत आपके द्वारा चुने गए सांप के अनुसार तय होती है। किंग कोबरा से बने व्यंजन की कीमत 180 डॉलर या लगभग 16,500 रुपये है। यहां सांप के अंगों से बने स्वास्थ्यवर्धक पेय भी उपलब्ध हैं। हांगकांग में सांप के व्यंजनों को एक अनोखी खाद्य संस्कृति के रूप में बढ़ावा दिया गया है। हालांकि, कई लोग इसे खतरनाक और अमानवीय मानते हैं।

वडोदरा मंडल पर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की इस वर्ष की पहली बैठक का आयोजन मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, वडोदरा में किया गया। बैठक के प्रारंभ में समिति के सचिव व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद समिति के अध्यक्ष एवं वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा संक्षिप्त प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी सदस्यों को मंडल की गतिविधियों एवं विकास कार्यों से अवगत कराया गया। श्री भडके ने माननीय सदस्यों को मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किये जा रहे स्टेशनों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतापनगर- जोबट क्षेत्र पर ट्रेनों

की सेक्शन स्पीड बढ़ाने के साथ-साथ स्टेशनों पर प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इसमें दिव्यांग फ्रेंडली सुविधा के दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि उधना स्टेशन पर यात्रियों के ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए उत्राण स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए वडोदरा मंडल द्वारा चलायी जा रही गोरखपुर एवं मऊ के लिए स्पेशल ट्रेन की जानकारी भी दी।

इस दौरान समिति सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की रेल समस्याओं, ट्रेनों के स्टॉपेज, विस्तार,नई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा मंडल के स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने सुझाव दिये । मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने सभी सदस्यों के सुझावों पर शीघ्र उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कहा कि यात्री सुविधाओं का विकास वडोदरा मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

इस आयोजित बैठक में माननीय सदस्यों में सर्वश्री निपम आर देसाई, श्री भरत आर गुप्ता, श्री नीलेशकुमार आई पटेल, श्री ईश्वर पी सज्जन, श्री वंदनकुमार बी पंड्या, श्री ओमकारनाथ तिवारी, श्री एम. हबीब लोखंडवाला, श्री इंद्रवदन एस जोशी, श्री व्यास मितलभाई कौशिकभाई और श्री राकेशचंद्र वी व्यास उपस्थित थे। बैठक के दौरान वडोदरा मंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद ⇌ मंगलुरु के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियाँ	प्रस्थान	आगमन
09424	अहमदाबाद - मेंगलुरु	27.02.2026 से 20.03.2026 तक	16:00 बजे (शुक्रवार)	20:00 बजे (दूसरे दिन)
09423	मेंगलुरु - अहमदाबाद	28.02.2026 से 21.03.2026 तक	22:30 बजे (शनिवार)	02:15 बजे (सोमवार)

होल्ट: नाडियाड, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, सवार्दा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, थिविम, करमाली, मडगांव, कनाकोना, करवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्देश्वर, भटकल, मुकाम्बिका रोड, बिंदूर, कुंदापुरा, उडुपी, मुल्की और सुरथकल स्टेशन दोनों दिशाओं में।

संरचना: AC 2-टियर, AC 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच।

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन नंबर 09424 के लिए बुकिंग सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर खुली हैं। ऊपर बताई गई ट्रेन स्पेशल ट्रेन के तौर पर स्पेशल किराए पर चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक और फॉलो करें
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

कर्ज के जाल ने छीनी तीन जिंदगियां, साहूकार के उत्पीड़न से टूटा सूरत का एक खुशहाल परिवार

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत शहर से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। वेसु इलाके के हैप्पी एलिगेंस अपार्टमेंट में रहने वाले बलमुकुंद परिवार ने साहूकार के कथित उत्पीड़न और आर्थिक दबाव से तंग आकर ऐसा भयावह कदम उठा लिया, जिसने एक ही झटके में तीन जिंदगियां छीन लीं और एक मासूम बेटी को जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। इस सामूहिक आत्महत्या की घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना का यह सिलसिला कब तक लोगों की जिंदगी निगलता रहेगा। जानकारी के अनुसार, बलमुकुंद परिवार के चार सदस्यों—पति बलमुकुंद, पत्नी प्रियंका और उनकी दो बेटियों पृथ्वी और भव्या—ने आत्महत्या के इरादे से जहर का सेवन कर लिया। यह कदम उन्होंने तब उठाया, जब वे कथित तौर पर एक साहूकार द्वारा लगातार किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न, धमकियों और आर्थिक दबाव से पूरी तरह टूट चुके थे। इस दर्दनाक घटना में बलमुकुंद, उनकी पत्नी प्रियंका और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी चमत्कारिक रूप से बच गई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। घर के अंदर का दृश्य बेहद दर्दनाक था, जहां एक परिवार की खुशियों का संसार पल भर में उजड़ चुका था। पुलिस ने मौके से एक तीन पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसने इस घटना के पीछे छिपे दर्द और मजबूरी की भयावह कहानी को उजागर कर दिया। इस सुसाइड नोट में परिवार ने अपनी आर्थिक तंगी और साहूकार द्वारा किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न का विस्तार से उल्लेख किया है। सुसाइड नोट में वैभव रुंगटा नामक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिस पर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया है। नोट में लिखा गया है कि साहूकार ने न केवल परिवार पर कर्ज चुकाने के लिए लगातार दबाव बनाया, बल्कि उनकी निजी संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया था। उसने पीड़ित की मोपेड जब्त कर ली थी और उनका क्रेडिट कार्ड भी अपने पास रख लिया था। इतना ही नहीं, आरोप है कि वह उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खुद खरीदारी कर रहा था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और अधिक खराब होती जा रही थी।

परिवार के लिए यह स्थिति केवल आर्थिक संकट नहीं थी, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अत्यंत पीड़ादायक थी। लगातार मिल रही धमकियों, अपमान और आर्थिक दबाव ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वे खुद को असहाय और बेबस महसूस करने लगे थे। आखिरकार, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने अपनी जिंदगी समाप्त करने जैसा कठोर और दुखद निर्णय ले लिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी वैभव रुंगटा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि साहूकार के उत्पीड़न से परेशान होकर ही परिवार ने यह कदम उठाया। पुलिस अब मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि बलमुकुंद परिवार एक साधारण और शांतिप्रिय परिवार था। वे किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे, लेकिन कभी किसी से कोई विवाद भी नहीं हुआ था। लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह परिवार इतनी गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजर रहा है।

यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह समाज के उस कड़वे सच को भी उजागर करती है, जहां आर्थिक शोषण और कर्ज का दबाव लोगों को आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है। साहूकारी और सूदखोरी की यह व्यवस्था कई बार लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। जब कर्ज केवल आर्थिक बोझ नहीं रह जाता, बल्कि मानसिक यातना का कारण बन जाता है, तब व्यक्ति खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगता है।

वर्तमान में पुलिस उस बेटी के बयान का इंतजार कर रही है, जो इस घटना में जीवित बच गई है। उसके बयान इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह स्पष्ट करने में मदद करेंगे कि परिवार किस हद तक उत्पीड़न का शिकार हुआ था। साथ ही, पुलिस सुसाइड नोट और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर समाज और प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आर्थिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कदम उठाने की कितनी आवश्यकता है। यह जरूरी है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को समय पर सहायता और सुरक्षा मिले, ताकि कोई भी परिवार इस तरह की भयावह त्रासदी का शिकार न हो।

सूरत की इस घटना ने कई अनुत्तरित सवाल छोड़ दिए हैं—क्या आर्थिक दबाव किसी की जिंदगी से ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या समाज और व्यवस्था समय रहते ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकती? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक कर्ज और उत्पीड़न का यह दुष्चक्र निर्दोष जिंदगियों को निगलता रहेगा। यह घटना एक चेतावनी है कि हमें केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी, ताकि कोई भी परिवार मजबूरी में मौत को गले लगाने के लिए विवश न हो।

दिल्ली में गर्मी की दस्तक, कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, बदलते मौसम ने बढ़ाई चिंता

(जीएनएस)। देश की राजधानी नई दिल्ली में मौसम ने अब धीरे-धीरे करवट लेनी शुरू कर दी है और गर्मी ने अपने शुरुआती संकेत देने शुरू कर दिए हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही दोपहर की तेज धूप लोगों को यह एहसास कराने लगी है कि सर्दियों का असर अब खत्म होने की कगार पर है और गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है। हालांकि सुबह और देर रात के समय अब भी हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जिससे मौसम में एक अजीब संतुलन बना हुआ है। दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंड के इस मिश्रित मौसम ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले सात दिनों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। गुरुवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। यह तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक माना जा रहा है और यह संकेत देता है कि इस बार गर्मी अपेक्षाकृत जल्दी दस्तक दे रही है।

मौसम विभाग ने केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए भी तापमान बढ़ने की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि इस सप्ताह इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य, दैनिक जीवन और ऊर्जा खपत पर पड़ सकता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, वैसे-वैसे बिजली की मांग और पानी की खपत भी बढ़ने की संभावना है।

इसी बीच देश के कई अन्य हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग रूप दिखा रहा है। जहां एक ओर उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण भारत और तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

इसके अलावा छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी 25 से 26 फरवरी के बीच हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इन राज्यों में होने वाली बारिश से तापमान में अस्थायी गिरावट आ सकती है, लेकिन तेज हवाओं और अचानक बदलते मौसम से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव मौसमी संक्रमण का हिस्सा है, जहां सर्दी से गर्मी की ओर मौसम का रुख बदलता है।

उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम अस्थिर बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 27 और 28 फरवरी के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे इन क्षेत्रों में ठंड का असर कुछ समय के लिए बना रह सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि बर्फबारी और बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं।

इसी बीच मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की है। पंजाब और ओडिशा के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और सुरक्षित गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है।

पश्चिम भारत के राज्यों में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। राजस्थान में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह तापमान फरवरी के महीने के लिए काफी अधिक माना जाता है और यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है। वहीं सिरोही में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिन और रात के तापमान में अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। दौसा में सर्वाधिक 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे स्थानीय तापमान में अस्थायी गिरावट देखने को मिली।

सूरत के नए सिविल अस्पताल में संविदा कर्मचारियों की मौजूदगी से जुड़े घोटाले की जांच की मांग की गई है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के नए सिविल अस्पताल में, श्रेणी-3 तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक, नकद विभाग के कर्मचारी और श्रेणी-4 सफाईकर्मी, नैनी और वार्ड बॉय के पद संविदा पर भरे जाते हैं। इन संविदा पदों पर अपेक्षित संख्या से कम कर्मचारियों की भर्ती के कारण वार्डों और अन्य विभागों में सफाई का काम ठीक से नहीं होता है और ठेकेदार तथा सूरत के सिविल अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन कितने कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए, इसके लिए कोई नियम या मानक नहीं है। सूरत के नए सिविल अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, ठेकेदार के कर्मचारी और साथ ही साथ नए सिविल अस्पताल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो वर्तमान में संविदा पर काम कर रहे हैं, इन सभी की मिलीभगत से उपस्थिति में गड़बड़ी की जा रही है और सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। प्रतिदिन कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और कितने कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा गया है, इसका निर्णय अगले दिन किया जाता है। इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी ने पिछले दिन अपना कर्तव्य निभाया था या नहीं। और किसी को भी यह जानने में रुचि नहीं है।

शून्य त्रुटि एजेंसी

सूरत के नए सिविल अस्पताल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके पद के अनुसार वेतन मिलता है। ऑल इंडिया सफाई मजदूर कांग्रेस के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत के. सोलंकी की मांग है कि

कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ।

राजस्थान की गांव ग्वाला योजना: 10,000 रुपये के वेतन पर ग्वालों की भर्ती शुरू

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आजकल राजस्थान सरकार की एक योजना खूब चर्चा में है, जिसका नाम है गांव ग्वाला योजना। इस योजना के तहत गाय चराने वाले चरवाहों की भर्ती की जा रही है और उन्हें इसके लिए भुगतान भी किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले के रामगंज मंडी के 14 गांवों में चरवाहों की नियुक्ति की है। सरकार ने पशुपालन की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए यह नई योजना शुरू की है।

शून्य त्रुटि एजेंसी

ये चरवाहे प्रतिदिन गांव की सभी गायों को सामूहिक रूप से चरागाह में ले जाएंगे और शाम को उन्हें वापस घर ले आएंगे। गायों को पूरे दिन चरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और शाम को उन्हें वापस गांव के घरों में भेज दिया जाएगा। प्रत्येक 70 गायों के लिए एक चरवाहा नियुक्त किया गया है। यदि गायों की संख्या बढ़ती है, तो उस गांव में अन्य चरवाहों को भी नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक चरवाहे को गायों को चराने के लिए 10,000 रुपये का वेतन मिलेगा। यह योजना गांव के दानदाताओं के सहयोग से चलाई जा रही है।

हर घर तक पहुंचा जीवन का अमृत: लाठ गांव में 'जल अर्पण दिवस' बना विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक

(जीएनएस)। गांव की पहचान सिर्फ उसके खेतों, घरों और लोगों से नहीं होती, बल्कि वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं ही उसकी असली तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। पानी उन सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जीवन का आधार है और यही विकास की पहली शर्त भी है। राजकोट जिले के उपलेटा तालुका स्थित लाठ गांव में हाल ही में मनाया गया 'जल अर्पण दिवस' केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उस लंबे संघर्ष, उम्मीद और परिवर्तन की कहानी का उत्सव था, जिसने गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। वर्षों तक पानी की समस्या से जूझने वाले इस गांव में अब हर घर तक नल से पानी पहुंचने लगा है, और यह उपलब्धि गांव के लोगों के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है।

करीब 43 लाख रुपये की लागत से तैयार की गई जल वितरण प्रणाली के पूर्ण होने के बाद जब धोराजी के प्रांत अधिकारी एन. एम. तरखला ने ग्राम पंचायत की जल समिति को 'जल कलश' भेंट किया, तो वह क्षण केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह जिम्मेदारी, विश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। यह जल कलश उस भरोसे का प्रतीक था, जो अब सरकार ने गांव के लोगों पर जताया है कि वे अपने संसाधनों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं और अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। इस अवसर पर गांव में उत्साह और गर्व का माहौल था। ग्रामीणों के चेहरों पर संतोष और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, क्योंकि अब उन्हें पानी के लिए लंबी दूरी तय करने या अनिश्चित स्रोतों पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं रही।

यह परिवर्तन जल जीवन मिशन के तहत संभव हुआ, जिसका उद्देश्य देश के हर ग्रामीण घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है। इस मिशन ने केवल पानी उपलब्ध कराने का काम नहीं किया, बल्कि गांवों में विकास की नई सोच और आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाई है। लाठ गांव इसका एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां अब पानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और स्थानीय जल समिति को सौंप दी गई है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर प्रबंधन मजबूत होगा, बल्कि ग्रामीणों में अपने संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना भी बढ़ेगी।

कार्यक्रम के दौरान प्रांत अधिकारी ने अपने संबोधन में पानी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को अपनाकर भविष्य के लिए जल संरक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण से नहीं होती, बल्कि उसके रखरखाव और सही उपयोग से होती है, और इसमें जनभागीदारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनका यह संदेश ग्रामीणों के दिलों को छू गया, क्योंकि वे जानते हैं कि अब यह जिम्मेदारी उनकी अपनी है।

इस कार्यक्रम में वास्मो की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, जिसने इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन और प्रबंधन में सहयोग किया। वास्मो के अधिकारियों ने बताया कि जब स्थानीय समुदाय को योजना की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसका संचालन अधिक प्रभावी और टिकाऊ होता है। इससे न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, बल्कि लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। यही कारण है कि लाठ गांव अब केवल पानी की समस्या से मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि वह आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ा है।

कार्यक्रम के दौरान जल कर प्रोत्साहन योजना के तहत उपलेटा और धोराजी तालुका के पांच-पांच गांवों को प्रशस्ति पत्र और लगभग 9.50 लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की गई।

सोना वायदा में 722 रुपये और चांदी वायदा में 4256 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा में 2 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 242602.57 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 29376.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 213221.58 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 40130 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2018.12 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 23025.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 160977 रुपये के भाव पर खूलकर, 161652 रुपये के दिन के उच्च और 160163 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 159969 रुपये के पिछले बंद के सामने 722 रुपये या 0.45 फीसदी की मजबूती के साथ 160691 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 151 रुपये या 0.12 फीसदी बढ़कर 128821 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 52 रुपये या 0.32 फीसदी बढ़कर 16257 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मार्च वायदा 158391 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159245 रुपये और नीचे में 157750 रुपये पर पहुंचकर, 739 रुपये या 0.47 फीसदी बढ़कर 158330 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 160200 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 160373 रुपये और नीचे में 157025 रुपये पर पहुंचकर, 157946 रुपये के पिछले बंद के सामने 656 रुपये या 0.42 फीसदी बढ़कर 158602 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी वायदाओं में 29376.42 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 213221.58 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 23025.62 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40130 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 265944 रुपये के भाव पर खूलकर, 270500 रुपये के दिन के उच्च और 263300 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 260744 रुपये के पिछले बंद के सामने 4256 रुपये या 1.63 फीसदी की तेजी के संग 265000 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 4955 रुपये या 1.88 फीसदी की तेजी के संग 268290 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 6030 रुपये या 2.29 फीसदी की मजबूती के साथ 268824 रुपये प्रति किलो बोला गया। मेटल वर्ग में 4943.21 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 22.1 रुपये या 1.88 फीसदी की तेजी के संग 1200.1 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 2.65 रुपये या 0.81 फीसदी गिरकर 326.5 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 95 पैसे या 0.31 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 304.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 20 पैसे या 0.11 फीसदी बढ़कर 186.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1404.65 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 6044 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 6073 रुपये और नीचे में 5970 रुपये पर पहुंचकर, 2 रुपये या 0.03 फीसदी बढ़कर 6010 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 2 रुपये या 0.03 फीसदी लुढ़ककर 6008 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 259.5 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 260.8 रुपये और नीचे में 257.4 रुपये पर पहुंचकर, 262.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.1 रुपये या 1.18 फीसदी घटकर 259 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 3.3 रुपये या 1.26 फीसदी औंधकर 259.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 940.7 रुपये पर खूलकर, 2.5 रुपये या 0.27 फीसदी बढ़कर 945 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 13181.36 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9844.25 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4366.69 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 228.96 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 47.50 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 293.31 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 675.87 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 698.10 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.34 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9476 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 74660 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31279 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 369670 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 62066 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10148 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 17340 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 55281 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 18785 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 27252 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 40019 पॉइंट पर खूलकर, 40277 के उच्च और 40019 के नीचले स्तर को छूकर, 349 पॉइंट बढ़कर 40130 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 3.4 रुपये की बढ़त के साथ 327.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.25 रुपये की गिरावट के साथ 17.3 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 135.5 रुपये की गिरावट के साथ 348 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 448.5 रुपये की बढ़त के साथ 17878 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.25 रुपये की बढ़त के साथ 16.31 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 372.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.8 रुपये की गिरावट के साथ 0.69 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 5.6 रुपये की बढ़त के साथ 321.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.25 रुपये की बढ़त के साथ 17.7 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 516 रुपये की गिरावट के साथ 1133.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 428 रुपये की गिरावट के साथ 2590 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.62 रुपये की गिरावट के साथ 38.25 रुपये हुआ।